



नई दिल्ली, लखनऊ और रायपुर से प्रकाशित

पायनियर



उत्तराखंड में भूमि
जिहाद, थूक जिहाद
नहीं चलेगा : धामी
राष्ट्रीय-9

www.dailypioneer.com

बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद के हालात अब चल रही राजनीतिक गोलियां

टीएन रघुनाथ। मुंबई

बाबा सिद्दीकी की हत्या में महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य को हिलाकर रख दिया है, जबकि राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारी अपने जोरों पर है। जहां सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ विपक्ष एकजुट होकर जवाबदेही की मांग कर रहा है, वहीं देश की वितीय राजधानी में हुई इस हत्या के निहितार्थ निश्चित रूप से चुनाव अभियान में गुंजेंगे, जो पहले से ही शुरू हो चुका है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है यह घटना मतदाताओं की भावनाओं को काफी प्रभावित कर सकती है, क्योंकि मुंबई के नागरिकों के लिए उनकी सुरक्षा और संरक्षा सर्वोपरि चिंता का विषय है। उद्धव ठाकरे-शरद पवार और कांग्रेस गठबंधन वाला विपक्ष इस घटना का राजनीतिक फायदा उठा सकता है और इसे राज्य में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार की कानून-व्यवस्था का पूरी तरह से ध्वस्त होना बता सकता है।

हत्या की निंदा करने वालों में विपक्षी दलों के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) भी शामिल है, जो सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। विपक्षी दल कांग्रेस ने हत्या की निंदा की है क्योंकि कांग्रेस सिद्दीकी



मुंबई में रविवार को बाबा सिद्दीकी (इजसेट) के घर के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मी, यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया। पीटीआई

की मूल पार्टी रही है जहाँ से उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था, जबकि अजित पवार का गुट उनकी वर्तमान पार्टी है। महाराष्ट्र में गृहमंत्री का पद संभाल रहे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी कड़ी आलोचना की गई है और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफलता का हवाला देते हुए उनसे इस्तीफा मांगा गया है। सिद्दीकी हाल ही में कांग्रेस से एनसीपी के अजित गुट में चले गए थे, और महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक दलों में उनके अच्छे संबंध थे, जिसमें शिवसेना और एनसीपी के दो अलग हुए गुट भी शामिल हैं।

मुंबई पुलिस ने शनिवार को तीन बार के विधायक बाबा सिद्दीकी की नृशंस हत्या के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया। जबकि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सिद्दीकी की हत्या पर उनके इस्तीफे की मांग करने के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर निशाना साधा। सिद्दीकी की हत्या में गिरफ्तार किए गए दो लोगों की पहचान हरियाणा के मूल निवासी गुरमेल बलजीत सिंह और उत्तर प्रदेश के धर्मराज कश्यप के रूप में करते हुए पुलिस ने कहा कि तीसरा संदिग्ध शिव कुमार फरार है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, हम तीसरे आरोपी की तलाश कर रहे हैं। इस बीच, दोनों आरोपियों की माताओं ने कहा है कि उन्हें नहीं पता था कि उनके बेटे क्या कर रहे थे और वे उनके संपर्क में नहीं थीं। गुरमेल सिंह के परिवार ने कहा कि उन्होंने 11 साल पहले ही उसे त्याग दिया था और उसके कृत्यों के लिए कड़ी सजा की मांग की। इस बीच, सिद्दीकी की हत्या को लेकर विपक्षी दलों की आलोचना के बीच, फडणवीस 'जिनके पास राज्य गृह विभाग है' ने शरद पवार द्वारा उनके इस्तीफे की मांग करने (शेष पृष्ठ 9)

नवरात्र खत्म, दुःस्वप्न शुरू

सौम्या शुकला। नोएडा

विजयादशमी की पूर्व संध्या पर, जब राष्ट्रीय राजधानी में दैवीय स्त्रीत्व और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जा रहा था, इस दौरान पायनियर की महिला रिपोर्टर को शनिवार रात उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर-75 में शराबियों की गुंडागर्दी और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जो इस त्योंहार को शराब पीकर लोगों की जान लेने का मनमर्जी करने का अवसर मानते हैं। इस संबंध में महिला पत्रकार के सामने एक और समस्या यह आई कि जब पहली बार मदद के लिए संपर्क किया गया, तो पुलिस ने सहाय्यता नहीं दिखाई।

सड़कों पर लोग रामलीला और रावण दहन का आनंद ले रहे थे, जो एक प्रतीकात्मक अनुष्ठान है जब हिंदू लोग सत्य की जीत का जश्न मनाने के लिए रावण के चतुर्दशों को जलाते हैं, उसी समय एक सफेद हुंडई आई-20 स्पोर्ट्स कार (यूपी15 सीडी6004) रात करीब 10 बजे अनियंत्रित तरीके से सड़कों पर दौड़ रही थी। देखने पर पता चला कि ड्राइवर बहुत ज्यादा नशे में थे।

सबसे पहले, वे सड़क के किनारे एक दुकान के अंदर घुस गए और आस-पास खड़े कई लोगों की जान जोखिम में डाल दी, जबकि मैं (महिला पत्रकार) और मेरा एक दोस्त दशरथ मेले से लौटने के बाद एक स्ट्रीट वेंडर से खरीदकर कुछ खा रहे थे।

शर्मनाक आंकड़े

दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न की दर चिंताजनक रूप से अधिक है, और अधिकांश मामले दर्ज नहीं किए जाते हैं। सितंबर 2022 से अगस्त 2023 तक फरीदाबाद में 2,666 शिकायतें दर्ज की गईं, गुरुग्राम में दर्ज मामलों में 12 फीसदी की वृद्धि हुई। दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर देश में सबसे अधिक 144.4 प्रति 100,000 दर्ज की गई, नोएडा में ऐसे अपराधों में 21 फीसदी की कमी आई।

जब मैं अपने दोस्त के साथ सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी, उस समय मैं सड़क के बाईं ओर थी, तभी कार मेरे पास से तेजी से गुजरी, तभी मेरे परिचित ने मुझे कार से कुचले जाने या रैसिंग कार से टकराने से बचाने के लिए किनारे पर खींच लिया। एक सेकंड के लिए, कार रुकी और अचानक से फिर से दौड़ने लगी। जब मेरा दोस्त उन कार वालों पर चिल्लाया, जबकि मैं कांप रही थी, इस चिंता में कि यह एक मौत का अनुभव जैसा था, दो राहगीर, जो सड़क के किनारे शराब पी रहे थे, इन लोगों ने मेरे दोस्त को गाली देना शुरू कर दिया। उन्होंने गाली-गलौज की और उसे ड्राइवरों पर चिल्लाने से मना किया, जैसे कि हम दूसरों के

जीवन को खतरे में डालने के लिए जवाब मांगने की गलती कर रहे हैं।

इस बात से चिंतित कि यह एक भयंकर लड़ाई और जान को जोखिम में डाल सकती है, मैं अपने दोस्त को दूसरी तरफ ले गई, तब तक ड्राइवर ने लोगों को पुलिस से घटनास्थल पर आने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहते हुए सुना होगा। उन्होंने अपनी कार को घटनास्थल के पास ही एक सोसाइटी की तरफ मोड़ दी। पुलिस को 112 पर कॉल करने पर, अधिकारियों ने संवेदनहीन तरीके से पूछा कि क्या हम इस पर रिपोर्ट दर्ज करेंगे। घटना के लगभग 20 मिनट बाद दो अधिकारियों के साथ एक पुलिस वैन घटनास्थल पर पहुंची। हालांकि, जब वे आए तो उन्होंने फिर से हमसे पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने को कहा, जबकि हमने उनसे तुरंत कुछ कार्रवाई करने को कहा, ताकि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हमने कहा, हम लोगों ने उन्हें यहीं सोसाइटी में तेजी से कार को ले जाते हुए देखा है। वे (पुलिसवाले) कम से कम यह पता लगाने की कोशिश करें कि क्या गाड़ी को पता है कि कार किसी प्लेट की है या नहीं। पुलिस अधिकारियों ने आधे-अधूरे मन से गाड़ी से कुछ सवाल पूछे, लेकिन हमें फिर से नोएडा के सेक्टर-113 पुलिस थाने में जाने को कहा गया। खराब मानसिक स्थिति के बावजूद हमने थाने जाकर शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया। पुलिस ने आश्वासन (शेष पृष्ठ 9)

वक्तव्य संयुक्त समिति को मिली 1.2 करोड़ ईमेल प्रतिक्रियाएं

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

वक्फ (संशोधन) विधेयक पर सोमवार को संसदीय पैनल के समक्ष नासिक के एक मंदिर के मुख्य पुजारी, तीन अधिकार और एक मुस्लिम संगठन के प्रतिनिधि अपने विचार साझा करने वालों में शामिल होंगे। वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति की बैठक सोमवार और मंगलवार को होनी है, जिसमें जमीयत उलेमा-ए-हिंद, दिल्ली और गोवा स्थित सनातन संस्था के प्रतिनिधियों की बात सुनी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के जगदीशका पाल को अध्यक्षता वाला पैनल नासिक के श्री कालाराम मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सुधीरदास महाराज की भी बात सुनेगा। इसके अलावा अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय, विशु शंकर जैन और अश्विनी सचदेवा भी पैनल के समक्ष विधेयक पर अपने विचार साझा करेंगे। सचदेवा हिंदू जनजाति समिति, गोवा का प्रतिनिधित्व करती हैं। कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनवर मणिपट्टी को भी मसौदा विधेयक पर अपनी राय साझा करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। मसौदा कानून के बारे में अपने-अपने दृष्टिकोण के लिए (शेष पृष्ठ 9)

दिवाली के लिए सज रही अयोध्या



बिस्वजीत बनर्जी। लखनऊ

अयोध्या दिवाली के लिए दीपोत्सव के लिए तैयार है, शहर में बड़े पैमाने पर सौंदर्यकरण की प्रक्रिया चल रही है। इस तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रमुख स्थानों पर सौर ऊर्जा से चलने वाली स्मार्ट लाइट लगाना है, जिसका प्रबंधन उत्तर प्रदेश नवीय एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा) द्वारा 300 करोड़ रुपये के बजट से किया जा रहा है। ये सौर लाइट अयोध्या बाईपास और महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर जाने वाली सड़क को रोशन करेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लंबे समय से अयोध्या को 'सौर शहर' में बदलने की कल्पना की है। घरों की छतों पर सौर ऊर्जा के पैनल लगाने सहित विभिन्न सौर ऊर्जा परियोजनाएं पहले से ही प्रगति पर हैं, और अयोध्या में कई पार्क और सड़कें अब सौर लाइटों से जगमगा रही हैं। यूपीनेडा इन स्मार्ट सौर लाइटों की स्थापना में तेजी ला रहा है, जिसमें

पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करने के लिए हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में 60 की योजना बनाई गई है। इसके अलावा, पीएनडीए अयोध्या बाईपास के दोनों किनारों और अन्य रणनीतिक स्थानों पर 58 स्मार्ट सौर लाइटें लगा रहा है। मंडलायुक्त आवास के पास 16, धर्मपथ के पास पार्क में 10 और मुक्ति धाम में छह लाइटें लगाई जा रही हैं। यूपीनेडा के परियोजना अधिकारी प्रवीण कुमार पांडेय ने पुष्टि की कि परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है और दिवाली तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि त्योहारों के लिए प्रमुख स्थल जगमगाएं।

इसके साथ ही अयोध्या में राम मंदिर के ऊपर 161 फुट ऊंचे शिखर का निर्माण तेजी से चल रहा है। शिखर की पहली परत पूरी हो चुकी है और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोशल मीडिया पर प्रगति की तस्वीरें साझा की हैं। मंदिर की नींव से तीसरी मंजिल तक की ऊंचाई 76 फीट है। शिखर इस संरचना से ऊपर उठेगा और मंदिर में काफी भव्यता जोड़ेगा। शिखर की ऊंचाई 85 फीट होगी और इसमें 29 परतें होंगी, जिनमें से प्रत्येक लगभग तीन फीट ऊंची होगी। लगभग 300 कुशल कारीगर इस परियोजना पर काम कर रहे हैं और प्रत्येक परत को लगभग एक सप्ताह में पूरा किया जाएगा। शिखर के निर्माण के बाद, इसके ऊपर 44 फुट का धर्म ध्वज (धार्मिक ध्वजस्तंभ) स्थापित किया जाएगा, जिसके साथ छह फुट का धार्मिक ध्वज भी होगा। इससे शिखर सहित मंदिर की कुल ऊंचाई लगभग 211 फीट हो जाएगी। शिखर का निर्माण फरवरी 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।

मां दुर्गा को विदाई



राजधानी नई दिल्ली में रविवार को दुर्गा पूजा उत्सव के समाजान के अवसर पर पूजा पंडाल में 'सिंदूर खेला' में एक-दूसरे को सिंदूर लगाती महिलाएं। फोटो: रंजन किशोर/पायनियर

उपभोक्ता को प्राथमिकता दे ओला : सीसीपीए

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म ओला को उपभोक्ता-अनुकूल बदलाव लागू करने का निर्देश दिया है। नियामक ने रविवार को यह निर्देश जारी किया जिसमें रिफंड विकल्प प्रदान करना और ऑटो राइड के लिए और रसदी प्रदान करना शामिल है। मुख्य आयुक्त निधि खरे के नेतृत्व में सीसीपीए ने पाया कि ओला धन वापसी के लिए किसी भी प्रश्न का विकल्प नहीं है, कंपनी सिर्फ वाहन के लिए कूपन कोड प्रदान करती है और उपभोक्ताओं को बैंक खाते में धन वापसी का विकल्प भी नहीं प्रदान करती है।

सीसीपीए ने एक बयान में कहा, यह तरीका उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करता है। बिना किसी सवाल के रिफंड नीति का मतलब यह नहीं हो सकता कि कंपनी लोगों को बस दूसरी सवारी लेने के लिए इस सुविधा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। नियामक ने ओला को अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुक की गई सभी ऑटो राइड के लिए बिल या चालान जारी करने का भी आदेश दिया, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत 'अनुचित व्यापार व्यवहार' के रूप में ऐसे

दस्तावेजों की अनुपस्थिति का हवाला दिया गया। सीसीपीए के हस्तक्षेप के बाद, ओला ने कई बदलाव लागू किए हैं, जिसमें इसकी वेबसाइट पर शिकायत और नोड्यूल अधिकारियों के संपर्क विवरण प्रदर्शित करना, बुकिंग के समय रद्दीकरण नीतियों और शुल्कों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना, सवारी रद्द करने के कारणों के लिए और अधिक विकल्प जोड़ना और किराया घटक टूटने को सार्वजनिक करना शामिल है। लागू किए गए अन्य बदलावों में ड्राइवरों को पिकअप और ड्रॉप दोनों स्थानों का पता दिखाना और त्वरित भुगतान के लिए ड्राइवरों के लिए संशोधित भुगतान चक्र शामिल थे। सीसीपीए ने जनवरी से अक्टूबर 2024 तक ओला के खिलाफ 2,061 शिकायतें दर्ज कीं, जिनमें ओवरबुकिंग, रिफंड में देरी और ड्राइवर से संबंधित समस्याएं शामिल हैं। सीसीपीए नियामक ने कहा, अपने नियामक हस्तक्षेप के माध्यम से, यह सुनिश्चित करने में दृढ़ रहा है कि ओला उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए स्थापित कानूनी ढांचे का पालन करे। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब सीसीपीए ने तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स और राइड-हेलिंग क्षेत्रों में उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्मों की जांच बढ़ा दी है।

पुरानी बसों के खराब होने से ट्रैफिक जाम बना जंजाल



राजेश कुमार। नई दिल्ली

● सड़कों पर लगातार दर्जनों बड़े वाहनों के बिगड़ने से थम जाता है यातायात, होता है डायवर्जन

सोशल मीडिया पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा लोगों से बस खराब होने के कारण लगने वाले जाम के कारण कुछ खास सड़कों से दूर रहने की सोशल मीडिया पर अपील करना आम बात है। ये घटनाएं बसों के रोजाना खराब होने की वास्तविक संख्या का एक छोटा सा हिस्सा हैं। बसों और माल ढोने वाले वाहनों का खराब होना दिल्ली में पीक ऑवर्स के दौरान ट्रैफिक जाम का एक बड़ा मुद्दा बन गया है।

परिवहन विभाग के सूत्रों ने बताया कि दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर स्कीम की दर्जनों बसें रोजाना सड़कों पर खड़ी रहती हैं। बस खराब होने के कारण भीषण जाम लग जाता है। इससे न केवल सड़क पर फसे दैनिक यात्रियों को असुविधा होती है, बल्कि वाहनों की गति धीमी होने और खड़े रहने से ट्रैफिक जाम भी होता है। त्योहारी सीजन के चलते भी यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। नजफगढ़ डिपो

के पास रविवार को एक बस के खराब होने से नजफगढ़-बहादुरगढ़ रोड पर यातायात प्रभावित रहा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, अनाज मंडी, नजफगढ़ के पास हाइवा ट्रक में दुर्घटना और आग लगने के कारण बहादुरगढ़-नजफगढ़ रोड पर यातायात प्रभावित हुआ। ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को बसों के खराब होने पर दो एडवाइजरी जारी कीं। पहली बार



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रविवार को भारत मंडपम का अचानक दौर से राष्ट्रीय राजधानी के बीचों-बीच यातायात थम जाने से भीषण जाम की स्थिति बन गई। मध्य से दक्षिणी दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे यात्रियों को असुविधा हुई, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट के कारण मुख्य सड़कें जाम रहीं। दोपहर और शाम को भारत मंडपम के आसपास घंटों सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू रहा और यात्रियों को अपने वाहनों में ही घंटों इंतजार करना पड़ा।

नजफगढ़ रोड पर धोली प्याऊ से द्वारका मोड़ की ओर जाने वाले कैरिजवे में उत्तम नगर चौक पर एक बस के खराब होने के कारण यातायात धीमा हो गया। दूसरी घटना में, रोहतक रोड पर टिकरी बाँडर से पीरागढ़ी की ओर जाने वाले कैरिजवे में मेट्रो पिलर नंबर 530 के पास एक बस के खराब होने के कारण

यातायात प्रभावित हुआ। ट्रैफिक पुलिस के शुक्रवार को सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, पीक ऑवर्स में वाहनों के खराब होने की पांच घटनाएं सामने आईं। सरिता विहार फ्लॉइडओवर के पास क्लस्टर बस के खराब होने के कारण आश्रम से बदरपुर की ओर जाने वाले कैरिजवे में मथुरा रोड (शेष पृष्ठ 9)

वीआईपी रूट लगने से लगा जाम, बढ़ी परेशानी

● भारत मंडपम में पीएम के दौरे के चलते आईटीओ के पास लगी वाहनों की लंबी लाइन

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

मध्य दिल्ली के लोगों को वीआईपी रूट लगने के कारण रविवार शाम को भीषण जाम और परेशानी का सामना करना पड़ा।

जानकारी के मुताबिक रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अचानक दौरे के कारण यातायात थम गया, जिसके कारण मध्य दिल्ली से लेकर दक्षिणी दिल्ली जाने वाले यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा, वहीं वीआईपी मूवमेंट के कारण कई मुख्य सड़कों पर जाम की स्थिति रही।

भारत मंडपम के आसपास की सड़कों पर दोपहर और शाम के समय



सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू होने के कारण अपने गंतव्य के लिए जा रहे यात्रियों को सड़क पर अपने वाहनों में बैठकर रास्ता साफ होने का इंतजार करते हुए लंबे जाम का अनुभव किया।

इस परेशानी का अनुभव कई यात्रियों ने साझा किया। एक महिला ने कहा, यातायात में बेतरीब बदलाव होने के कारण हम मध्य दिल्ली से दक्षिणी दिल्ली का सफर कई घंटों में पूरा करना पड़ा। यात्रा जाम में फंसने

के कारण बेहद तकलीफ देह साबित हुई। एक अन्य ने कहा कि इंडिया गेट के आसपास की मुख्य सड़कें जाम रहीं। उसने कहा, यह दुखद है कि हम आम लोग अचानक वीआईपी दौरे के कारण सामान्य रूप से यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। अगर उनकी सुरक्षा भी नहीं है, मुझे यह पसंद नहीं है कि नागरिकों के रूप में हम मूल्यवान नहीं हैं और जिन राजनेताओं को हमने काम करने के लिए वोट दिया है, उन्हें

का दौरा किया। इस साइट पर उनके अचानक दौरे के कारण प्रोटोकॉल के अनुसार शहर की सड़कों पर व्यापक सुरक्षा योजनाएं बनाई गई थीं।

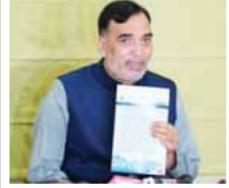
एक कामकाजी पेशेवर समय पर अपने कार्यालय नहीं पहुंच पाई क्योंकि वह भारत मंडपम के सामने वाली सड़क पर फंस गई और उसने शिकायत की कि एक सामान्य नागरिक के समय का कोई मूल्य नहीं है। उसने कहा, मैं एक काम पूरा करने के बाद भारत मंडपम से आईटीओ अपने कार्यालय आ रही थी।

हालांकि, मेरी कार भारत मंडपम के पास लाल बत्ती पर लगभग 20 मिनट तक फंसी रही, जबकि उसी समय ट्रैफिक पुलिस ने आईटीओ से भारत मंडपम तक यातायात का प्रवाह रोक दिया गया था। यह पछूने पर कि क्या उसका समय उतना मूल्यवान नहीं है। मुझे यह पसंद नहीं है कि नागरिकों के रूप में हम मूल्यवान नहीं हैं और जिन राजनेताओं को हमने काम करने के लिए वोट दिया है, उन्हें

इस तरह का अनुचित लाभ मिलता है। उसने शिकायती लहजे में कहा, एक यात्री जो अक्सर बसों से यात्रा करता है, ट्रैफिक पुलिस ने बस स्टॉप पर अराजकता के हालात पैदा कर दिए थे, उन्होंने हमें बस में चढ़ने के लिए मुश्किल से एक मिनट दिया और बसों को उस क्षेत्र के पास एक बस स्टॉप पर जल्दी से आगे बढ़ने के लिए कहा, जहां प्रधानमंत्री का दौरा था। हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब पूर्वी दिल्ली के यातायात को कम करने के लिए पुनर्विकसित प्रगति मैदान क्षेत्र में यात्रियों को ऐसी असुविधाएं हुई हों।

जी-20 जैसे बड़े आयोजनों की मेजबानी के लिए बनाए गए भारत मंडपम में आने वाले वीआईपी लोगों के लिए अक्सर सुरक्षा उपाय किए जाते हैं, लेकिन ये उपाय यात्रियों के लिए हैं, लेकिन ये उपाय यात्रियों के लिए हैं, क्योंकि वे घंटों तक अपने वाहनों में ही फंसे रहते हैं, जिससे उनकी आवाजाही बाधित होती है।

दशहटा बाद भी स्वच्छ हवा में सांस ले रहे लोग : गोपाल राय



● पर्यावरण मंत्री ने कहा, दिल्ली में एक्वआई पहले से बेहतर

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रविवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में दशहटा उत्सव के बावजूद लोग स्वच्छ हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छे, संतोषजनक और मध्यम वायु गुणवत्ता वाले दिनों की संख्या बढ़ रही है, जो कहीं न कहीं प्रदूषण प्रबंधन में सुधार का संकेत है।

राय ने यह भी कहा कि दशहटा के बाद दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी से बाहर रहा, हालांकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार शहर की वायु गुणवत्ता दोपहर 12 बजे 225 अंक के साथ खराब श्रेणी में रही थी। राय ने रविवार को संवाददाताओं से कहा कि हर साल दशहटा के बाद हवा की गुणवत्ता आमतौर पर खराब श्रेणी में दर्ज की जाती थी लेकिन इस साल दिल्ली में हवा साफ रही। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में दिल्ली में जनवरी से 12 अक्टूबर के बीच 200 दिन अच्छी, संतोषजनक या मध्यम वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है, जबकि 2016 में



सिर्फ 109 दिन ऐसा हुआ था। राय ने कहा कि यह प्रदूषण प्रबंधन में प्रगति का एक संकेत है। उन्होंने इस सुधार का श्रेय दिल्ली सरकार के प्रयासों और जनता के समर्थन को दिया। राय ने कहा कि बिना लॉकडाउन के यह हासिल करना शहर के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

दिल्ली में शनिवार को दशहरे के दिन एक्वआई 155 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है। मंत्री ने दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बिगड़ने के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दावे की भी आलोचना की और कहा कि पार्टी को डेटा की समीक्षा करनी चाहिए।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि सोमवार से दिल्ली के अंदर धूल प्रदूषण पैदा करने वालों पर किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जाएगी। अगर कोई भी डस्ट पॉल्यूशन फैलाता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 7 अक्टूबर से दिल्ली सरकार द्वारा एंटी डस्ट कैम्पेन शुरू किया गया है। इसके तहत मैंने खुद कई निर्माण साइटों का निरीक्षण किया और वहां नियमों का उल्लंघन होता पाया। इसके

बाद मैंने दिल्ली में अलग-अलग जगहों पर काम कर रही 120 निर्माण एजेंसियों के साथ दिल्ली सचिवालय में बैठक कर उन्हें नियमों की विस्तृत जानकारी दी है। मेरा सखी से निवेदन है कि वायु प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई में सभी लोग दिल्ली सरकार का सहयोग करें और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की मुहिम में सहभागी बनें।

गोपाल राय ने कहा कि मैंने 30 अगस्त को सबसे पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि एनसीआर राज्यों की एक संयुक्त मीटिंग बुलाई जाए। बैठक में आईआईटी कानपुर समेत अन्य एक्सपर्ट्स, संबंधित विभागों को भी बुलाया जाए, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है और भाजपा भी चुप है। इसके बाद मैंने 10 अक्टूबर को दोबारा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को चिट्ठी लिखी है। उसका भी जवाब नहीं आया है। मेरा उनसे निवेदन है कि आपकी व्यवस्था बहुत ज्यादा है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री होने के नाते दिल्ली के लोगों को प्रदूषण की लड़ाई में सहयोग करना आपकी भी जिम्मेदारी है। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि अगर बारिश की वजह से प्रदूषण का स्तर सुधर रहा है।

दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए बनाया कृत्रिम घाट

नई दिल्ली। आप सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने मां दुर्गा की मूर्तियों के पर्यावरण अनुकूल विसर्जन के लिए नेहरू प्लेस और गुलाबी बाग में विस्तृत व्यवस्था की। दिल्ली सरकार ने आस्था कुंज में मां दुर्गा की मूर्तियों के विसर्जन हेतु कृत्रिम घाट के निर्माण के साथ-साथ श्रद्धालुओं के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं रोशनी के लिए लाइटों की व्यवस्थाएं तथा पानी की व्यवस्था का पर्याप्त इंतजाम किया। मां दुर्गा की मूर्तियों के विसर्जन हेतु दो जैसीबी मशीनों की व्यवस्था भी दिल्ली सरकार की ओर से की गई, ताकि सभी श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के मां दुर्गा की बड़ी-बड़ी मूर्तियों का विसर्जन भी आसानी से और पूरी श्रद्धा के साथ कर सकें।



गुलाबी बाग में कृत्रिम तालाब में मां दुर्गा की मूर्तियों का पर्यावरण अनुकूल विसर्जन किया गया। फोटो: रंजन डिमरी

महिला से यौन शोषण मामला

आप-उपराज्यपाल के बीच बढ़ी तकरार



उपराज्यपाल आवास की तरफ जाती विधायक राखी बिडलान

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

महिला डॉक्टर के साथ यौन शोषण के आरोप पर मेडिकल सुपरिटेण्डेंट (एमएस) पर एफआईआर और उसकी गिरफ्तारी की मांग लेकर दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष राखी बिडलान के नेतृत्व में आप का महिला प्रतिनिधिमंडल रविवार को एलजी से मिलने पहुंचा, लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं की। राखी बिडलान ने कहा कि एलजी पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। राखी ने कहा कि एलजी निवास के बाहर घंटों खड़े रहे, लेकिन हमसे मिलने कोई नहीं आया। महिला डॉक्टर का बीते एक साल से शोषण हो रहा है। उसकी गुहार सुनने के बजाय उसका तबादला कर दिया गया। इस दौरान विधायक धनवती चंदेला, प्रीति

आप की महिला प्रतिनिधिमंडल से नहीं मिले एलजी

तोमर, वंदना कुमारी, भावना गौड़ के साथ आम आदमी पार्टी की महिला पार्षद मौजूद रहीं। उपाध्यक्ष राखी बिडलान ने कहा कि यह बहुत शर्म और हेरानी की बात है कि आप दिल्ली की चुनी हुई महिला प्रतिनिधि एलजी साहब को पहले से सूचना देकर उनके आवास पर मिलने पहुंची। उन्होंने कहा कि आज जब हम पीडित महिला डॉक्टर की आवाज बुलंद करने, हिम्मत बढ़ाने और दुर्व्यवाहारे करने वाले की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहुंचे तो हमें रोकने के लिए सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया।

वांगचुक समेत 21 हिरासत में

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस ने रविवार को यहां लद्दाख भवन के बाहर प्रदर्शन करने को लेकर जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और 20 अन्य प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया।

अधिकारियों ने बताया कि वांगचुक और उनके साथ अनशन कर रहे करीब 20 से 25 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है एवं उन्हें मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया। मौके पर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने दलील दी कि वे प्रदर्शन नहीं कर रहे थे बल्कि शांतिपूर्वक बैठे थे। एक वरिष्ठ

लद्दाख भवन के बाहर पुलिस बल तैनात

पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के पास लद्दाख भवन के बाहर बैठने की अनुमति नहीं है। उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए अर्जी दी है। उस विचार किया जा रहा है। हमने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। वांगचुक लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर अपने समर्थकों के साथ लोह से दिल्ली आए हैं। उन्हें दिल्ली पुलिस ने 30 सितंबर को सिंचू बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया था।

12 वित्त पोषित कॉलेजों की तीसरी किस्त को मंजूरी

तीसरी तिमाही में लगभग सौ करोड़ रुपये जारी किए

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

आप सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के अपने वित्तपोषित कॉलेजों के लिए तीसरी तिमाही में भी लगभग 100 करोड़ रुपये जारी किए हैं। मुख्यमंत्री आतिशी ने इन 12 वित्तपोषित कॉलेजों की तीसरी तिमाही की किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है।

बता दें कि आप सरकार की ओर से दावा किया गया है कि इन वित्तपोषित कॉलेजों के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 400 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। आप सरकार के आने के बाद से इन कॉलेजों को दिए जाने वाले



बजट में 3 गुणा से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि जबसे दिल्ली में केजरीवाल के नेतृत्व की सरकार आई है। हर साल बजट में शिक्षा को सबसे बड़ा हिस्सा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि स्कूलों के साथ-साथ आप सरकार ने उच्च शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया और

तीन नई यूनिवर्सिटी खोली और मौजूदा यूनिवर्सिटीज का विस्तार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की उच्च शिक्षा में दिल्ली सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित 12 दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

2014-15 में इन कॉलेजों को 132 करोड़ रुपये आवंटित किये गए थे। आप सरकार का आरोप है कि इन कॉलेजों में पिछले कुछ सालों से वित्तीय कुप्रबंधन के कई मुद्दे सामने आए। लेकिन, आप सरकार ने ये निर्णय लिया है कि मैनेजमेंट के कारण, एडमिनिस्ट्रेशन की गलतियों की वजह से इन कॉलेजों के शिक्षकों और विद्यार्थियों का नुकसान नहीं होना चाहिए।

बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा फंड जारी करने से उनके रुके हुए वेतन, मेडिकल बेनिफिट, पेंशन बेनिफिट के जो बिलों का भुगतान रुका हुआ था वह अब हो सकेगा।

मूर्ति विसर्जित करते समय डूबने से किशोर की मौत

एक की मौत, दूसरा घायल, हमलावर फरार

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

हर्ष विहार इलाके में दो भाइयों को बाइक सवार तीन युवकों की नसीयत देना महंगा पड़ा। मामले में एक भाई को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा जबकि दूसरा भाई घायल हुआ है। हसले के दौरान लोग तमाशाबीन बनी रहे, किसी ने उनको बचाने का प्रयास नहीं किया। शनिवार को हिमांशु और अंकुर दो भाई दशहरा मेला देखने जा रहे थे तभी बाइक पर आ रहे तीन युवक भीड़ में तेजी से बाइक चला रहे थे। दोनों भाई बाइक

मेला देखने जा रहे दो भाइयों पर चाकू से हमला

एक की मौत, दूसरा घायल, हमलावर फरार

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

हर्ष विहार इलाके में दो भाइयों को बाइक सवार तीन युवकों की नसीयत देना महंगा पड़ा। मामले में एक भाई को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा जबकि दूसरा भाई घायल हुआ है। हसले के दौरान लोग तमाशाबीन बनी रहे, किसी ने उनको बचाने का प्रयास नहीं किया। शनिवार को हिमांशु और अंकुर दो भाई दशहरा मेला देखने जा रहे थे तभी बाइक पर आ रहे तीन युवक भीड़ में तेजी से बाइक चला रहे थे। दोनों भाई बाइक



मृतक का फाइल फोटो

से बाल-बाल बचे और उन्होंने बाइक सवारों को सही से चलने की नसीहत दी। आरोपियों ने दोनों भाई अंकुर और हिमांशु पर चाकू से ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। अंकुर के छाती, पेट और जांघ पर चाकू लगे घायल हिमांशु अपने भाई को ई-रिक्शा में लेकर अस्पताल पहुंचा जहां डॉक्टरों से उसे मृत घोषित कर दिया जबकि हिमांशु को प्राथमिक उपचार

के बाद छुट्टी दे दी गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस आस-पास में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से मामले की जांच कर रही है।

जानकारी के मुताबिक मूलरूप से डिंडू खेड़ा शांमली का रहने वाला अंकुर अपने परिवार के साथ बी ब्लॉक प्रताप नगर में रहता था। उसके परिवार में पिता कृष्ण पाल मां सुनीता एक बहन और भाई हिमांशु है।

अंकुर गाजियाबाद फिटर से आईटीआई कर रहा है। हाल में ही उसकी नौएड में एक कंपनी में जॉब लगी थी। पुलिस आस-पास में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से मामले की जांच कर रही है।

नियमों को ताक पर रखकर कराये अवैध निर्माण : विजेंद्र

नेता प्रतिपक्ष ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर लगाया आरोप

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली



केजरीवाल ने अपने आवास में शामिल करने के लिए आसपास के बंगलों और फ्लैटों को ध्वस्त कर दिया, जो पूरी तरह से अवैध है। उन्होंने कहा कि लेआउट प्लान की अवैधता के बिना सरकारी संपत्ति पर अवैध निर्माण करना किसी भी रूप में अस्वीकार्य है।

उन्होंने कहा, इसके अलावा, न तो अधिकतम ग्राउंड कवरेज और न ही बिल्डिंग नियमों के तहत अधिकतम एफएआर (फ्लोर एरिया

रेशियो) सीमा का पालन किया गया है। गुप्ता के अनुसार, उपराज्यपाल कार्यालय ने पुष्टि की है कि 6, फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले में किए गए संशोधनों के लिए कोई मंजूरी नहीं ली गई थी। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि आवास से सटे 45 और 47 राजपुर रोड स्थित आठ टाइप-बी फ्लैटों को ध्वस्त करके और 8-ए और 8-बी फ्लैग स्टाफ रोड स्थित दो बंगलों को फ्लैग कुल मिटाकर लगभग 25,000 वर्ग गज - मुख्यमंत्री के लिए लगभग 40,000 वर्ग गज (आठ एकड़) क्षेत्र में आलीशान शोश इन बनाया गया है। उन्होंने कहा, मल सार सारकारी संपत्तियों को मिलाने के लिए किसी सक्षम अधिकारी से अनुमति नहीं ली गई और इसलिए, ये संपत्तियां अभी भी सरकारी रिर्कोर्ड में बंगला नंबर 45, 47 राजपुर रोड और 8-ए और 8-

बी, फ्लैग स्टाफ रोड के रूप में दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि 6, फ्लैग स्टाफ रोड के साथ विलय होने के बावजूद, वे आधिकारिक तौर पर अलग-अलग संपत्तियों के रूप में मौजूद हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आवास पर कुछ हड़दो भी प्रभावित होने के साथ ही सामान्य कामकाज भी प्रभावित हो सकता है। यह बात विश्व गठिया दिवस पर मैक्स हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिसिस्ट और जॉइंट रिप्लेसमेंट विभाग के प्रधान निदेशक और प्रमुख डॉ. एल तोमर का। डॉ. तोमर के अनुसार, 70 फीसदी से अधिक मामलों में ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने के गठिया का सबसे आम कारण है। इसमें घुटने की दोनों हड्डियों के बीच का अंतर कम हो जाता है। सामान्य तौर पर घुटने के गठिया के मरीजों में अक्सर रोड़ की हड्डी में विकृति देखी जाती है

‘रोड़ की हड्डी को प्रभावित करती है घुटने की गठिया’

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

घुटने के उपचार में देरी और घुटने के गठिया के लक्षणों को नजरअंदाज करने के चलते रोड़ की हड्डी भी प्रभावित होने के साथ ही सामान्य कामकाज भी प्रभावित हो सकता है। यह बात विश्व गठिया दिवस पर मैक्स हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिसिस्ट और जॉइंट रिप्लेसमेंट विभाग के प्रधान निदेशक और प्रमुख डॉ. एल तोमर का। डॉ. तोमर के अनुसार, 70 फीसदी से अधिक मामलों में ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने के गठिया का सबसे आम कारण है। इसमें घुटने की दोनों हड्डियों के बीच का अंतर कम हो जाता है। सामान्य तौर पर घुटने के गठिया के मरीजों में अक्सर रोड़ की हड्डी में विकृति देखी जाती है

क्योंकि जब मरीज झुकें हुए पैर की विकृति के साथ चलना जारी रखते हैं तो इससे रोड़ की हड्डी पर अधिक दबाव पड़ता है।

डॉ. एल तोमर ने गठिया को पहचान करने और शुरुआती जांच व इलाज से दीर्घकालिक परेशानियों से बचा जा सकता है। 60 फीसदी से अधिक मरीज अपने घुटने के इलाज में अंतिम चरण तक देरी करते हैं जिससे उनके घुटनों को अधिकतम सीमा तक नुकसान पहुंचता है। हम नियमित रूप से घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी की सलाह देते हैं यदि रोगी को चलने या दैनिक जीवन की गतिविधियों में कमी महसूस होती है और एक्स-रे में ऑसैट दर्ज आर्टिक्युलर स्पेस का पूर्ण या लगभग पूर्ण नुकसान दिखाई देता है।

संक्षिप्त समाचार

‘समाज के लिए 40 वर्षों से समर्पित है ब्रह्मकुमारी’



नई दिल्ली। ब्रह्माकुमारी एक विश्वव्यापी आध्यात्मिक आंदोलन है जो पिछले 88 वर्षों से व्यक्तिगत सुधार और विश्व नवीनीकरण के प्रति समर्पित है। आरके पुरम स्थित ब्रह्माकुमारी केंद्र की प्रभारी बीके बहन अनीता 40 वर्षों से समाज की भलाई के लिए समर्पित हैं। इस केंद्र में सभी धर्मों के 100-150 लोग नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करते हैं। इस अवसर पर माउंट आबू स्थित ब्रह्माकुमारी मुख्यालय के मुख्य वक्ता बीके सूरज भाई, बीके गीता और बीके रूपेश मौजूद थे। कार्यक्रमों में योग भट्टी (ध्यान शिविर) और एक सार्वजनिक कार्यक्रम समाज का समाधान के माध्यम से समस्याओं को हल करने के लिए एक परिचय शामिल थी। इस कार्यक्रम से शहर के हजारों से अधिक लोग लाभान्वित हुए।

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में यूनानी चिकित्सा शिविर

नई दिल्ली। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बती कांग्रेस की ओर से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में यूनानी उपचार जनता के द्वार मिशन 2025 के तहत 96 वां निःशुल्क यूनानी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन डॉक्टर सैयद फारूक ने किया। उन्होंने कहा कि यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा देने में तिब्बिया कॉलेजों की भूमिका को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बती कांग्रेस के महासचिव डॉ. सैयद अहमद खान ने कहा कि निःशुल्क यूनानी चिकित्सा शिविर के माध्यम से यूनानी को घर घर और हर वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। शिविर में जिन डॉक्टरों ने मरीजों का चहकअप किया और अपनी नसीयत में शिविर में डॉ. एहसान अहमद हिंदी, डॉ. मिर्जा आसिफ बेग, डॉ. मुहम्मद अरशद, डॉ. अदुस्सलाम, हकीम आफताब आलम, डॉ. शकील, डॉ. कमरुद्दीन, औसाफ मुहम्मद खान शामिल हुए।

बवाना की फैक्ट्री में लगी आग, कोई हताहत नहीं

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में रविवार को एक फैक्ट्री में आग लग गई दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अधिकारी ने बताया, हमें सुबह नौ बजकर 20 मिनट पर बवाना औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर-3 में एक फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली। आग बुझाने के लिए कुल 16 दमकल गाड़ियों को भेजा गया।

मोदी की लाओस यात्रा

भारत-आसियान सम्मेलन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लाओस यात्रा 21वें भारत-आसियान सम्मेलन में भाग लेने के लिए थी। मोदी ने कहा कि यह यात्रा दक्षिणपूर्व एशियाई देशों 'आसियान' से राजनयिक संबंध मजबूत करने को लक्षित थी। कनेक्टिविटी बढ़ाने तथा संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा में समग्र 10 सूत्री कार्यक्रमों की घोषणा की जिसका उद्देश्य भारत-आसियान साझेदारी और मजबूत करना था। यह पहल न केवल वैश्विक अनिश्चितता के समय में क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने का महत्व रेखांकित करती है, बल्कि इसमें 21वीं शताब्दी का परिदृश्य विकसित करने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया कि इक्कीसवीं शताब्दी 'भारत-आसियान की होगी।' प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया कि भारत और आसियान देशों के बीच संबंध और सहयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। ये संबंध खासकर विभिन्न क्षेत्रों में जारी टकराव तथा विश्व स्तर पर बढ़ रहे तनाव को देखते हुए जरूरी हैं। उन्होंने जोर दिया कि भारत-आसियान मैत्री, समन्वय संवाद तथा सहयोग ऐसे समय जरूरी हैं जब दुनिया के अनेक हिस्से टकरावों और तनावों का सामना कर रहे हैं। यह शिखर सम्मेलन भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के एक दशक पूरे होने पर उसकी समीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इस नीति ने पिछले दस साल में भारत-आसियान



व्यापार को दूना कर 130 बिलियन डालर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अनेक प्रमुख क्षेत्रों में आसियान देशों से व्यापक संबंधों का दृष्टिकोण पेश किया है। पहलों में से एक कनेक्टिविटी बढ़ाना है जिसके लिए सात आसियान देशों तथा भारत के बीच सीधी उड़ानें शुरू की जा रही हैं। इस कदम से यात्रा और व्यापार आसान होगा जिससे इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ाव और मजबूत होगा। तकनीक के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के साथ 'फिनटेक कनेक्टिविटी' शुरू करने की घोषणा की जो आसियान देशों के साथ व्यापक सहयोग का एक उदाहरण पेश करती है। इस पहल से तकनीकी प्रगति को गति मिलेगी तथा वित्तीय समावेशन बढ़ेगा जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक संबंधों पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार और इंडोनेशिया के साथ साझा विरासत को मजबूत किया जा रहा है। यह क्षेत्रीय इतिहास तथा पहचान मजबूत करने व उसके संरक्षण को भारतीय प्रतिबद्धता के अनुरूप है। प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौते-पेटिंगा को पूरा करने की समीक्षा की जिससे दोनों पक्षों के बीच ज्यादा आर्थिक संभावनायें पैदा होंगी। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में आदान-प्रदान पर भी जोर दिया। आसियान देशों के 300 से अधिक छात्रों को नालन्दा विश्वविद्यालय में स्कारलरशिप से लाभ मिला है जिससे शिक्षा क्षेत्र में संबंध और मजबूत होंगे। दक्षिण चीन सागर में समुद्री विवादों के बढ़ने तथा म्यांमार में जारी संकट से खास चिन्ता पैदा हो गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने 'इंडो-पैसिफिक ओसेन्स इनीशियेटिव' पर जोर दिया है जिसमें क्षेत्रीय स्थायित्व व सुरक्षा सुनिश्चित करने को रेखांकित किया गया है। मानवीय सहयोग के साथ यह दृष्टिकोण प्राकृतिक विभीषिकाओं के समय आसियान देशों की सहायता के लिए भारत की प्रतिबद्धता प्रकट करता है। भारत का दृष्टिकोण जन-केन्द्रित है तथा टिकाऊ विकास के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट करता है जो दोनों क्षेत्रों में नागरिकों की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं के अनुरूप है। भारत और आसियान देशों के बीच शताब्दियों पुरानी विरासत और मूल्यों का साझा है जिनको पुनर्जीवित करने का समय आ गया है।

साथ जुड़ाव और मजबूत होगा। तकनीक के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के साथ 'फिनटेक कनेक्टिविटी' शुरू करने की घोषणा की जो आसियान देशों के साथ व्यापक सहयोग का एक उदाहरण पेश करती है। इस पहल से तकनीकी प्रगति को गति मिलेगी तथा वित्तीय समावेशन बढ़ेगा जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक संबंधों पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार और इंडोनेशिया के साथ साझा विरासत को मजबूत किया जा रहा है। यह क्षेत्रीय इतिहास तथा पहचान मजबूत करने व उसके संरक्षण को भारतीय प्रतिबद्धता के अनुरूप है। प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौते-पेटिंगा को पूरा करने की समीक्षा की जिससे दोनों पक्षों के बीच ज्यादा आर्थिक संभावनायें पैदा होंगी। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में आदान-प्रदान पर भी जोर दिया। आसियान देशों के 300 से अधिक छात्रों को नालन्दा विश्वविद्यालय में स्कारलरशिप से लाभ मिला है जिससे शिक्षा क्षेत्र में संबंध और मजबूत होंगे। दक्षिण चीन सागर में समुद्री विवादों के बढ़ने तथा म्यांमार में जारी संकट से खास चिन्ता पैदा हो गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने 'इंडो-पैसिफिक ओसेन्स इनीशियेटिव' पर जोर दिया है जिसमें क्षेत्रीय स्थायित्व व सुरक्षा सुनिश्चित करने को रेखांकित किया गया है। मानवीय सहयोग के साथ यह दृष्टिकोण प्राकृतिक विभीषिकाओं के समय आसियान देशों की सहायता के लिए भारत की प्रतिबद्धता प्रकट करता है। भारत का दृष्टिकोण जन-केन्द्रित है तथा टिकाऊ विकास के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट करता है जो दोनों क्षेत्रों में नागरिकों की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं के अनुरूप है। भारत और आसियान देशों के बीच शताब्दियों पुरानी विरासत और मूल्यों का साझा है जिनको पुनर्जीवित करने का समय आ गया है।

सूचना अधिकार में व्यावहारिक सुधार

सूचना अधिकार कानून-आरटीआई अपनी स्थापना के 19 साल पूरे कर रहा है। इसके नियमों में संशोधन कर इसका दायरा बढ़ाना तथा सुनिश्चित करना जरूरी है कि यह अपना उद्देश्य प्रभावी रूप से पूरा करे।

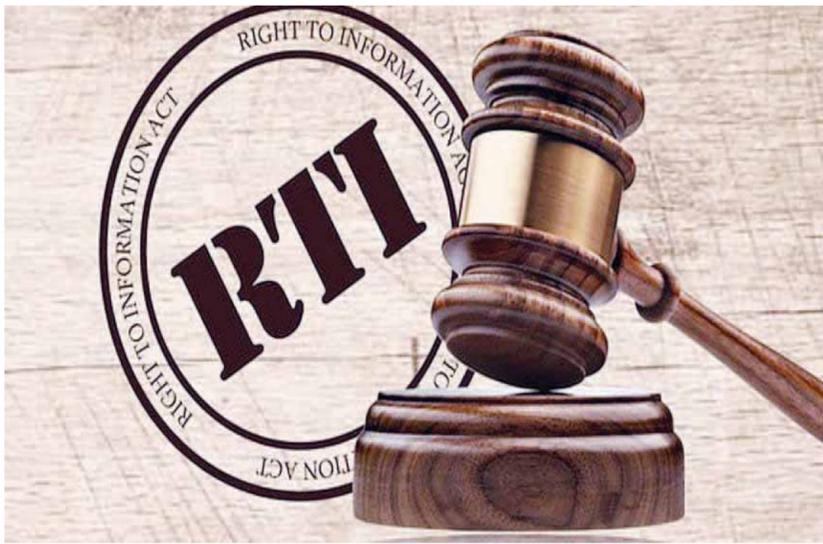


सुभाष चंद्र अग्रवाल
(लेखक, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं)

सूचना अधिकार कानून-आरटीआई अपनी स्थापना के 19 साल पूरे कर रहा है। समय आ गया है कि इसके नियमों में संशोधन कर इसका दायरा बढ़ाना तथा सुनिश्चित करना जरूरी है कि यह अपना उद्देश्य प्रभावी रूप से पूरा करे। सूचना अधिकार कानून-आरटीआई एक्ट को 12 अक्टूबर, 2005 को लागू किया गया था। यह भारत में सरकार की पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम था। पिछले वर्षों में इस कानून ने अनेक भ्रष्टाचार मामलों तथा अनेक घोटालों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने नागरिकों को सार्वजनिक अधिकारियों से सहायता मांगने के लिए सशक्त बनाया है। लेकिन जहां कानून ने असंदिग्ध रूप से महत्वपूर्ण सुधार लाने में सहायता की है, वहीं स्वयं कानून के बजाय आरटीआई नियमों में कुछ संशोधन और सुधार जरूरी हो गए हैं।

इसने कानून के दुरुपयोग को रोकने, प्रक्रियाओं को सहज और गतिशील बनाने तथा अदालतों पर बोझ घटाने में सहायता मिलेगी। कानून का दुरुपयोग रोकने तथा अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए ये सुधार जरूरी हैं। आज आरटीआई नियमों में कुछ संशोधन और सुधार जरूरी हो गए हैं।

इसके कारण अनावश्यक अपीलें होती हैं तथा अदालतों में इसे चुनौतियां दी जाती हैं। केन्द्रीय सूचना आयोग-सीआईसी को आरटीआई अपीलों से निपटने का काम दिया गया है, लेकिन यह अक्सर फर्जी मामलों से दबा रहता है जिसके कारण व्यवस्था बाधित होती है तथा असली शिकायतों के समाधान में विलंब होता है। खासकर सार्वजनिक-निजी साझेदारी-पीपीपी, खेल संस्थानों तथा सहकारिताओं के मामले में आरटीआई नियमों में संशोधन से यह दबाव काफी सीमा तक घट सकता है। पीपीपी, खेल संस्थानों तथा



सहकारिताओं को आरटीआई कानून के अंतर्गत सार्वजनिक अधिकारी घोषित करने से काफी समय और संसाधन बचाए जा सकते हैं। ये उद्यम अक्सर भारी मात्रा में सार्वजनिक धन प्रयोग करते हैं और उनको आरटीआई के दायरे से बाहर रखने के कारण पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। उनको कानून में शामिल करने से न केवल जवाबदेही बढ़ेगी, बल्कि ऐसे मामलों की संख्या में भी कमी आएगी जो सूचना आयुक्तों व अदालतों में पहुंचते हैं। इससे पूरी आरटीआई प्रक्रिया सहज बनेगी। सरकार को आरटीआई में खास क्षेत्र आर्बिट्रिजेशन के लिए जाने चाहिए। सरकारी जमीनों के आर्बिटन तथा आवास आर्बिटनों के मुद्दे पर ध्यान देना जरूरी है। अनेक सरकारी-स्वामित्व वाली संघटियों को सस्ती दरों पर आर्बिटन किया जाता है जिससे पक्षपात या भ्रष्टाचार संबंधी चिन्ता पैदा होती है।

इसे संबोधित करने के लिए ऐसे सभी आर्बिटनों को आरटीआई कानून के अंतर्गत समीक्षा के क्षेत्र में लाया जाना चाहिए। विलंब होता है। खासकर सार्वजनिक-निजी साझेदारी-पीपीपी, खेल संस्थानों तथा सहकारिताओं के मामले में आरटीआई नियमों में संशोधन से यह दबाव काफी सीमा तक घट सकता है। पीपीपी, खेल संस्थानों तथा

आर्बिटन हतोत्साहित होंगे तथा जनता की नजर से बच नहीं सकेंगे। इससे नागरिकों को सवाल पूछने और निगरानी का अवसर मिलेगा कि सार्वजनिक संसाधनों का आर्बिटन कैसे किया जाता है। इससे पारदर्शी प्रशासन को बढ़ावा मिलेगा। उच्च पदों संबंधी आरटीआई प्रार्थनाओं को सहज बनाया जाना चाहिए।

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्रियों को अक्सर ऐसी आरटीआई प्रार्थनापत्र मिलते हैं जिनका संबंध सीधे उनके कामकाज से होना जरूरी न हो। क्षमता में सुधार के लिए कार्यालयों को केवल ऐसी आरटीआई प्रार्थनाओं पर गौर करना चाहिए जिनका संबंध सीधे उनकी भूमिका से हो। दूसरे प्रकार के आरटीआई प्रार्थनापत्रों को प्राथमिकता से संपर्क करें। इस उपाय से उच्च पदों पर बोझ कम होगा तथा यह भी सुनिश्चित होगा कि नागरिकों को सही स्रोत से सूचनायें मिल सकें।

निजी क्षेत्र के बैंकों को आरटीआई के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। लंबे समय से वित्तीय क्षेत्र में ज्यादा पारदर्शिता की आवश्यकता महसूस की जा रही है। यह खासकर हालिया घोटालों तथा वित्तीय प्रबंधन के कारण जरूरी हो गया है। जहां सार्वजनिक क्षेत्र बैंक आरटीआई के दायरे

में आते हैं, वहीं निजी क्षेत्र कानून के दायरे से बाहर है। सार्वजनिक धन का निजी बैंकों के माध्यम से बढ़ता उपायों तथा अर्थव्यवस्था में उनकी बढ़ती सहभागिता के कारण यह चिन्ता काफी विषय है। इस कमी को दूर करने के लिए निजी क्षेत्र बैंकों को आरटीआई कानून शुरू कराना जरूरी है। इससे नागरिकों को उनके वित्तीय व्यवहारों के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा तथा इस क्षेत्र में जवाबदेही बढ़ेगी। आरटीआई फीस को मानक बनाने तथा उसका दुरुपयोग रोकना जरूरी है। वर्तमान आरटीआई ढांचे के सामने राश्यों में प्रार्थना फीस में असंगति एक बड़ी समस्या है। आरटीआई फीस को पूरे देश में 50 रुपये किया जाना चाहिए जिसमें 20 फोटोकॉपी पेजों की लागत शामिल हो।

इसके साथ ही अपीलों के लिए फीस समाप्त की जानी चाहिए। इन परिवर्तनों से नागरिकों के लिए प्रक्रिया सरल बनेगी तथा विभिन्न राश्यों में विभिन्न स्तरों का भ्रम दूर होगा। लेकिन कुछ निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा आरटीआई प्रार्थनाओं के दुरुपयोग पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, अनेक ठेकेदार गरीबी रेखा के नीचे वाले-बीपीएल कामगारों का प्रयोग कर उनके माध्यम से आरटीआई प्रार्थनायें करते हैं ताकि फीस

से बचा जा सके। इसे रोकने के लिए बीपीएल प्रार्थियों के लिए मुफ्त प्राविधान 20 पेजों तक सीमित किया जाना चाहिए। अतिरिक्त पेज होने पर एक मामूली धनराशि ली जानी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि व्यवस्था का दुरुपयोग न हो तथा वास्तव में वंचित लोगों को सूचना प्राप्त करने के लिए ज्यादा फीस न देनी पड़े। सूचना अधिकार कानून तक वास्तविक प्रार्थियों की पहुंच बढ़ाने के लिए पूरी प्रक्रिया का अधिकाधिक डिजिटलीकरण किया जाना चाहिए। आरटीआई प्रक्रिया को सहज और सुगम बनाने के लिए पूरे देश के पोस्टऑफिसों को आरटीआई प्रार्थनाओं को मुफ्त भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए।

इससे नागरिकों, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को बिना डाक खर्च की चिन्ता किए अपने आरटीआई प्रार्थनापत्र भेजने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही आरटीआई सूचना मांगने के लिए आईडी प्रूफ को अनिवार्य किया जाना चाहिए। पंजाब और हरियाणा जैसे कुछ राश्यों ने ऐसी व्यवस्था लागू की है। इसे अनिवार्य रूप से पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। इससे आरटीआई व्यवस्था का दुरुपयोग काफी सीमा तक थमेगा तथा यह सुनिश्चित होगा कि वास्तव में जरूरतमंद लोग ही आरटीआई कानून के माध्यम से आवश्यक सूचनायें मांगें। 'आनलाइन आरटीआई पोर्टल' को शुरू करना आरटीआई को जनता के निकट ले जाने में अत्यधिक सहायक सिद्ध होगा। देश के सभी राश्यों को नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर-एनआईसी द्वारा डिजाइन की गई आरटीआई वेबसाइटें जारी करनी चाहिए।

इससे पूरी आरटीआई व्यवस्था का मानकीकरण होगा तथा इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि आरटीआई सूचनायें मांगने वालों को सुविधा मिलेगी। इन पोर्टलों पर 'आटो ईमेल प्रतिक्रिया' तथा 'एलटर्न' की सुविधा दी जानी चाहिए। इससे आरटीआई सूचनायें मांगने वालों को अपनी प्रार्थनाओं पर कार्यवाई की स्थिति बहुत आसानी से पता चल जाएगी। सूचना के क्षेत्र में आरटीआई के लिए नियमों को समाप्त करने की जरूरत है। इनमें कुछ राश्यों द्वारा लागू किए नियम हैं। दिल्ली आरटीआई एक्ट जैसे राज्य कानूनों को समाप्त कर पूरे देश में राष्ट्रीय आरटीआई कानून लागू किया जाना चाहिए।

चिन्ता से मुक्ति पाने की आवश्यकता

चिन्ता से निपटने के लिए माइंडफुलनेस, मानसिक लचीलापन और तनाव से राहत देने वाली गतिविधियां जरूरी हैं।



रवि वलूरी
(लेखक, रेलवे से संबंधित हैं)

समय के पास एक प्रतिष्ठित संस्थान से प्रबंधन की डिग्री थी। मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के बाद, वह मार्केटिंग के 4पी में पारंगत था। अपने जीवन के इस मोड़ पर, युवा प्रशिक्षु ने कंपनी में शामिल होने, अत्यधिक वेतन पाने और कुछ समय में शहर के एक अप-मार्केट इलाके में एक आलीशान संपत्ति हासिल करने के बारे में कल्पना की। लेकिन अंतिम बाधा - साक्षात्कार को सफलतापूर्वक पार करने के बारे में उसके मन में झिझक का एक तत्व था। चूंकि मन वर्तमान क्षण में नहीं था और इसके बजाय भविष्य पर केंद्रित था, इसलिए वह चिंतित और लगातार उत्तेजित

रहता था। इस प्रकार, वह संतुलन, संतुलन या समभाव की स्थिति में नहीं था। इस बीच, सिद्धार्थ, उनके स्कूल के साथी ने वास्तुकला में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और शहर की एक प्रसिद्ध वास्तुशिल्प फर्म में प्रशिक्षुता प्राप्त की। हालांकि, सिद्धार्थ इमारतों को डिजाइन करने से संतुष्ट नहीं था। उनके पास एक ज्वरग्रस्त मन था जो मनोरंजन डिजाइन नामक एक नए क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए तड़प रहा था। इस युवा ने खुद को सिखाया और अत्याधुनिक और नए कोशल सेट हासिल किए। नए अर्जित ज्ञान से मजबूत होकर उन्होंने दूरदर्शी और सरल ग्राफिक्स, रेखाचित्र और पेंटिंग से युक्त एक पोर्टफोलियो तैयार किया। फिर भी, मानसिक रूप से वह चिंतित, तनावग्रस्त और तनावग्रस्त थे कि भविष्य में क्या होने वाला है। चिन्ताजनक परिस्थितियों से पहले आशंकित होना एक सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है क्योंकि यह वर्तमान क्षण में नहीं है। कई व्यक्ति पत्नीह और तैयारी जैसे



हो जाते हैं। हमेशा पेट के क्षेत्र में मंथन होता है और मन चिन्ता से ग्रस्त हो जाता है। घातक शस्त्रागार रखने वाले अर्जुन कौरवों की विशाल सेना को देखकर स्तब्ध हो गए। यह तब भी, जब भगवान कृष्ण उनके सारथी थे। कुरुक्षेत्र में टकराव से पहले शून्य घंटे में, उन्होंने

अपने हथियार रख दिए। पूर्ण योद्धा धर्म और द्वेष के बीच अंतर नहीं कर सका। भगवान कृष्ण के विश्वरूप दर्शन और दिव्य गीत - भगवद गीता के माध्यम से उनके मन में मौजूद राक्षस अंततः दूर हो गए। मनोवैज्ञानिकों ने ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए दो-

आयामी रणनीति विकसित की है, पहला, स्थिति की बारीकी से निगरानी करके और तुरंत और प्रभावी कार्यवाई करके और दूसरा, स्थिति से बचकर और उसे कूट करके। निगरानी में कई सक्रिय कदम उठाना शामिल है जो मन को तैयारी में मदद करते हैं। किसी महत्वपूर्ण घटना से पहले पहले से और अच्छी तरह से अभ्यास की गई तैयारी; यह तपस्या है और कोई भी इस आधार पर आराम नहीं कर सकता।

मन को दृढ़ और मजबूत होना चाहिए, प्रसिद्ध धनुर्धर अर्जुन की तरह निरंतर अभ्यास करना चाहिए। इस प्रक्रिया में, व्यक्ति मन को अव्यवस्थित करता है और चिन्ता और भय के बोझ से छुटकारा पाता है। टीकाकरण तकनीक एक और प्रभावी रणनीति है। एक व्यक्ति लगातार अभ्यास और भूमिका निभाने के माध्यम से तनाव के खतरों से खुद को बचाता है। इससे उम्मीदवार मानसिक रूप से मजबूत हो जाता है और वह पूरे आत्मविश्वास और विश्वसनीयता के साथ जांच और मूल्यांकन के लिए तैयार

हो जाता है। इसके अलावा, सकारात्मक व्यवहार अपनाया नौमूल्य है। इसके अलावा, कुछ ऐसी तरकीबें और रणनीतियां हैं जो उपरोक्त को बढ़ाने में मदद करती हैं। शारीरिक गतिविधि में डूब जाना समझदारी और चतुराई है। इसमें लंबी सैर करना, तैराकी करना, जिम जाना, कोई खेल खेलना या मन को तनावमुक्त करने के लिए योगिक तकनीक सीखना शामिल हो सकता है। ये गतिविधियां एंडोर्फिन रिलीज करती हैं जो मन को शांत करती हैं। साथ ही, व्यक्ति तराशा हुआ और स्मार्ट दिखाना देगा। खुश रहने के और भी तरीके हैं। उदाहरण के लिए, आर्ट ऑफ लिविंग के हैप्पीनेस प्रोग्राम में शामिल होकर सुदर्शन क्रिया की अनूठी लयबद्ध सांस लेने की तकनीक सीखें जो शरीर और मन को शांत करती हैं। वर्तमान क्षण में बने रहने के लिए प्राणायाम और ध्यान की विभिन्न तकनीकें सीखें। केवल जब कोई इंसान वर्तमान क्षण में होता है, तो वह चिन्ता से बचा रहता है और अंगुचित और कठिन परिस्थितियों का प्रबंधन कर पाता है?

आप की बात

सराहनीय निर्णय

मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा स्कूलों में किताबी शिक्षा के साथ-साथ व्यावहारिक और तकनीकी शिक्षा दिए जाने का निर्णय सराहनीय है। जिस प्रकार साईंस में पढ़ाई के साथ-साथ प्रैक्टिकल द्वारा हर चीज को अच्छी तरह समझाया जाता है, वैसे ही अन्य विषय के छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ जीवनोपयोगी शिक्षा दी जानी चाहिए। इसी प्रकार विभिन्न व्यवसायों संबंधी जानकारी भी छात्रों को दी जानी चाहिए। उनको बताया जाना चाहिए कि किस व्यवसाय या विनिर्माण के लिए कहां से कच्चा माल आता है। उसे बनाने में उपयोग में आने वाली मशीनरी और बेचने का पूरा ज्ञान यदि छात्र जीवन में ही मिल जाए

हरियाणा की राजनीति

हरियाणा की राजनीति में विकास और जवाबदेही के आधार पर एक नई दृष्टि का उदय हो रहा है। इस नए दौर में पारंपरिक राजनीति के उपाय और नीतियां अब प्रभावी साबित नहीं हो रही हैं। हरियाणा की राजनीति में जो मौजूदा बदलाव देखने को मिल रहा है, वह केवल एक चुनावी लहर नहीं बल्कि जनता की बदलती सोच का सटीक प्रतिबिंब है। अब वह दौर बीत चुका है जब जातिगत समीकरण और भावनात्मक नारे मतदाताओं को प्रभावित कर जाते थे। हरियाणा के मतदाता, खासकर युवा पीढ़ी अब विकास की सटीक दिशा की मांग कर रहे हैं। वे इसका आंकलन सिर्फ वोटों से नहीं, बल्कि ठोस नतीजों से कर रहे हैं। नेताओं को यह समझ लेना चाहिए कि अब पारंपरिक राजनीति की चालें काम नहीं करेंगी। आज जनता डिजिटल युग में है जहां हर छोटी-बड़ी बातों पर नजर रखी जाती है। लेकिन क्या यह बदलाव राजनीति के तात्कालिक समीकरणों को बदल देगा या फिर अगले चुनाव तक सब कुछ पुराने ढर्रे पर लौट जाएगा? यह सवाल हरियाणा के राजनीतिक नेतृत्व के सामने है। जनता अब सड़कों और पुलों से आगे बढ़कर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में सुधार चाहती है। स्पष्ट है कि हरियाणा के मतदाता अब नतीजे देखने लगे हैं।

- अमनीश कुमार गुप्ता, आजमगढ़

सुरक्षित रेल यात्रा

भारत का विशाल रेल नेटवर्क है, लेकिन आये दिन होने वाली रेल दुर्घटनाओं से आमजन चिंतित है। ट्रेनों को बेपटरी करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। लेकिन सजग रेल ड्राइवर्स ने अनेक दुर्घटनायें रोकने में सफलता पाई है। इन घटनाओं की जांच रेलवे के सुरक्षा आयुक्तों, पुलिस और एनआईए को करनी चाहिए। रेल मंत्रालय को कम वेतनमान पर रेलवे ट्रेक की निगरानी के लिये खलासियों की नियुक्तियां करनी चाहिए। लोगों की सुरक्षित रेल यात्रा सुनिश्चित करने के लिए ट्रेन को स्टेशन से रवाना करने से पहले उसकी तकनीकी जांच इंजीनियरों या तकनीक में अच्छी तरह प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा

मोहन भागवत का आह्वान

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आह्वान किया है कि हिंदूओं में एकजुटता जरूरी है। उन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण दिया कि जब हिंदू इकट्ठा हुआ तो बचाव हुआ। आरएसएस प्रमुख चाहते हैं कि भारत में रहने वाले सभी हिंदूओं को मिलकर साथ रहना चाहिए। उनका यह आह्वान स्वागत योग्य है। लेकिन हिंदू समाज की सामाजिक संरचना के कारण यह बेहद जटिल मुद्दा भी है। हिंदू समाज जाति, संप्रदाय और गोत्र में बंटा हुआ है और इनके बीच भेदभाव साफ दिखाई देता है। बहुत सी जातियों को सवियों तक दबाकर रखा गया है और आज भी उन पर अत्याचार होते हैं। आरएसएस को हिंदू धर्म में फैली सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने की दिशा में अपने प्रयास तेज करने चाहिए। हालांकि, आरएसएस अपनी स्थापना के समय से ही इन प्रयासों में लगा है, पर इतिहास की विकृत सोच तथा निहित स्वार्थी तत्वों की वर्चस्व की इच्छा के कारण यह काम आसान नहीं है। इस दिशा में संघर्षरत आरएसएस अपनी स्थापना के सौ वर्ष पूरे कर रहा है।

- वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

संगठित रहकर ही कर पाएंगे खुद की और देश की भी सुरक्षा: योगी

● संगठित रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे: मुख्यमंत्री

लखनऊ/गोरखपुर। मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब हम संगठित रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। छुआछूत, अशुभ्यता को दूर कर एकजुट रहेंगे खुद को और राष्ट्र की भी सुरक्षा कर सकेंगे। हमें उन पाखंडों से दूरी बनाकर रहना है जिससे चलते गुलामी का दंश झेलना पड़ा और आक्रांताओं को हमारे धर्म स्थलों को खंडित करने तथा सामाजिक ताने बाने को छिन भिन्न करने का मौका मिला। सीएम योगी शनिवार शाम मानसरोवर रामलीला मैदान में श्री श्री रामलीला समिति, आर्यनगर की तरफ से आयोजित प्रभु श्रीराम के राजतिलक समारोह को संबोधित कर रहे थे। सभी लोगों को विजयादशमी की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संगठित न रहने के कारण ही गुलामी के अलग अलग कालखंड में कभी काशी में विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर और मथुरा में श्रीकृष्ण

मंदिर को अपवित्र करने दुस्साहस आक्रांताओं ने किया। हम परतंत्र होंगे तो फिर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता सिर्फ राजनीतिक ही नहीं होती। बल्कि वह सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की वाहक भी होती है। इसलिए हमें संगठित होकर स्वतंत्रता दिलाने वाले अनेकानेक बलिदानियों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संगठित रहने के लिए, संगठन की ताकत दिखाने के लिए आवश्यक है कि हम जाति, मत, संप्रदाय, भाषा, छुआछूत जैसे भेदभाव से दूर रहें। इसी संदेश से लोगों को जोड़ने के लिए अयोध्या में जहां 500 वर्षों के बाद प्रभु श्रीराम का भव्य मंदिर बना है तो वहीं श्रीराम की कथा को देने वाले महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या के एयरपोर्ट का नामकरण किया गया है। अयोध्या में रसोईगृह माता शबरी के नाम पर बनी है तो यात्री विश्रामनाथ भगवान राम के आभिन सखा निषादराज के नाम पर। यह सामाजिक एकता भारत की विरासत का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि श्रृंगवेरपुर

श्रीनाथ जी का विशिष्ट पूजन कर गोरक्षपीठाधीश्वर ने की लोक कल्याण की प्रार्थना

● मंदिर के शक्तिपीठ में मां जगत जननी की पूजा करने के बाद शुरू हुआ विजयादशमी का अनुष्ठान

लखनऊ/गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में विजयादशमी पर्व के अनुष्ठान का शुभारंभ शनिवार प्रातःकाल श्रीनाथ जी (शिवावतार, गुरु गोरक्षनाथ) के विशिष्ट पूजन अनुष्ठान से हुआ। नाथपंथ की परंपरा का अनुसरण करते हुए गोरक्षपीठाधीश्वर के विशेष परिधान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीनाथ जी की विधि विधान से पूजा-आराधना की।

मं भगवान राम और निषादराज की गले मिलती प्रतिमा का निर्माण सरकार करवा था तब भारत में सन् 2025 में प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुम्भ का आयोजन भी विरासत के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन होगा।



तदुपरांत गोरखनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित सभी देव विग्रहों का विशिष्ट पूजन किया।

सीएम योगी ने कहा कि दुनिया में कहीं अन्य जगह जब सभ्यता का नामोनिशान नहीं था तब भारत में सभ्य सनातन समाज अस्तित्व में था। सनातन समाज कभी विपन्न बिखरे पड़े हैं। इन विषाणुओं को हमें कतई नहीं रहा। बुद्धि और वैभव में सदैव अग्रणी

रहा। साजिश के तहत क्षेत्र, जाति, भाषा, मत आदि के नाम पर मध्यकाल में उसे विभाजित किया गया जिसके विषाणु आज भी यत्र-तत्र बिखरे पड़े हैं। इन विषाणुओं को हमें कतई पनपने नहीं देना है। सीएम ने कहा कि हमें

जगतजननी की पूजा की और इसके बाद गोरखनाथ मंदिर के गर्भगृह में जाकर महायोगी गोरखनाथ जी के समक्ष हाजिरी लगाई। मंदिर के गर्भगृह में उन्होंने विशिष्ट पूजन किया और गुरु गोरखनाथ जी की आरती उतारी। उन्होंने मंदिर में प्रतिष्ठित सभी देव विग्रहों का भी विशिष्ट पूजन किया। गोरक्षपीठाधीश्वर ने करबद्ध होकर श्रीनाथ जी और सभी देव विग्रहों की परिक्रमा भी की और प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना की। नाथपंथ के परंपरागत विशेष वाद्य यंत्र नागफनी, शंख, ढोल, घंट, डमरू की गूंज से पूरा मंदिर परिसर भक्ति भाव में उल्लसित रहा।

संगठित होकर सकारात्मक दिशा में राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से जुड़ना है। व्यक्तिगत स्वार्थ कभी भी राष्ट्र से बढ़कर नहीं हो सकता। हमारा हर काम देश के नाम होना चाहिए। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए

हुआ आंदोलन भी इसी की प्रेरणा देता है।

राम मंदिर निर्माण के लिए हुए आंदोलन का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज को याद कर भावुक हो गए। उनके पूज्य गुरुदेव का आखिरी सपना मंदिर निर्माण को साकार होते देखना था। उनके जीवन के अंतिम क्षणों में जब विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल जी उनसे मिलने आए तब उन्होंने उनसे यही कहा था, अशोक जी राम मंदिर निर्माण कब तक हो पाएगा। एक बार मंदिर निर्माण देख लेते तो जन्म धन्य हो जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जब राम मंदिर बन गया है तो उनके गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज समेत अनगिनत संतो को तसल्ली हो रही होगी। सीएम ने कहा कि विरासत के संरक्षण और विकास की यात्रा मोदी के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ी है। देश और दुनिया में रहने वाले सनातनीयों, भारतीयों को इस पर गर्व होता है। पांच साल पहले कौन मानता था कि अयोध्या में जन्मभूमि पर प्रभु श्रीराम के मंदिर का निर्माण हो पाएगा।

भाजपा राज में बिगड़ती कानून व्यवस्था चिन्ताजनक: प्रमोद तिवारी

लखनऊ। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने भाजपा राज में बिगड़ती कानून व्यवस्था को चिन्ताजनक करार दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र के मुम्बई में पूर्व मंत्री बाबा सिददीकी की शूटर्स द्वारा निर्मात हत्या को निन्दनीय करार दिया है, और कहा कि बीजेपी के शासनकाल में विधायक तक सुरक्षित नहीं रह गये हैं। वहीं उन्होंने देश की लगातार खस्ताहाल हो रही अर्थव्यवस्था को लेकर भी मोदी सरकार पर तगड़ा प्रहार किया, और सरकार की विफलताओं पर तंज कसा। विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि सरकार के कुप्रबन्धन के कारण बिजली उत्पादन तथा आपूर्ति में सर्वाधिक खराब प्रदर्शन हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसके चलते देश के औद्योगिक उत्पादन में गिरावट हो रही है। सांसद प्रमोद तिवारी ने आईआईपी के हवाले से जारी ताजा रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि औद्योगिक उत्पादन 0.1 प्रतिशत घट गया। वहीं उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के बेपटरी पर होने के कारण डॉलर के मुकाबले रूपया सबसे निचले स्तर पर आ पहुंचा है। उन्होंने कहा कि सरकार की कमजोर घरेलू अर्थव्यवस्था के प्रबंधन की



खामी के चलते रूपया पहली बार ग्यारह पैसे की गिरावट में आ खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार के गैरजिम्मेदाराना रूख के चलते वैश्विक बाजार में भी देश की अर्थव्यवस्था की साख पर आंच आ रही है। वहीं उन्होंने भाजपा पर राजनैतिक प्रतिशोध की भाषा में नियंत्रण रखने की भी कड़ी नसीहत दी। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने कहा कि आतंकवाद पर कुछ बोलने से पहले भाजपा को अपने अतीत में झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ने आजादी में योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बंद नहीं किया तो कांग्रेस भी शालीनता के साथ आतंकवाद को लेकर भाजपा को सड़कों पर बेनकाब करेगी।

भाजपा की नीतियां विनाशकारी हैं:अखिलेश

लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डॉ. राममनोहर लोहिया की 57वीं पुण्यतिथि पर उनको नमन करते हुए कहा है कि हम उनके सपनों का समाजवादी भारत बनाने का सपना पूरा करने का संकल्प लेते हैं। डॉ. राममनोहर लोहिन ने देश में हर तरह से भेदभाव के खालमें, और जाति तोड़ने का आव्हन किया था। हर स्तर पर हो रहे भेदभाव का विरोध किया था। समाजवादी व्यवस्था से ही गरीबी मिटेगी। पढ़ाई में भेदभाव मिटेगा। डॉ. राममनोहर लोहिया की दाम बांधो नीति से ही महंगाई, गरीबी दूर होगी। लोहिया ने ससक्रांतिक के माध्यम से समाज में खुशहाली का रास्ता दिखाया था। अखिलेश यादव गोमती नगर स्थित डॉ राम मनोहर लोहिया पार्क में पहुंचकर समाजवादी चिन्क डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण के पश्चात् एकत्र हजारों कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं जनसमुदाय को संबोधित कर रहे हैं। डॉ. लोहिया की पुण्यतिथि पर राजधानी लखनऊ में मुख्य कार्यक्रम लाहिया पार्क में हुआ। लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर में विधायक रविदास मेहरोत्रा ने डॉ. लोहिया की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। प्रदेश के विभिन्न जनपदों और अन्य प्रदेशों में भी समाजवादी पार्टी के कार्यलयों में डॉ. राममनोहर लोहिया को श्रद्धांजलि दी गई।



अखिलेश ने कहा कि भाजपा की नीतियां विनाशकारी हैं। संविधान से बनी हर चीज ने कहा रेलवे में सुधार की बड़ी-बड़ी बातें की जो नफरत की राजनीति करते हैं। वे भेदभाव करते हैं। यह वे लोग हैं जो धर्म जातियों को लड़ाकर राजनीति करना चाहते हैं। श्री यादव ने कहा कि किसी देश की मुद्रा का पतन, अर्थव्यवस्था के पतन का प्रतीक होता है। भाजपा सरकार अर्थव्यवस्था की बदहाली के डूटे आंकड़ों की कितनी भी मोटी परत बिछा दे लेकिन दुनिया के सामने सच खुल ही जाता है। उन्होंने कहा कि जब सरकार यह कह रही है कि 5 ट्रिलियन डालर की एकोनोमी है, अगर हमारी अर्थव्यवस्था आगे

बढ़ रही है तो आखिरकार हंगर इन्डेक्स पर हम कहां खड़े हैं। 105वां स्थान पर श्री यादव ने कहा रेलवे में सुधार की बड़ी-बड़ी बातें की गई थीं। परिणाम क्या निकला? 2 कोई रिकार्ड तोड़ रही है तो पेपर लीक के बाद ट्रेन एक्सपीटेंट। यादव ने कहा कि कल जेपीएनआईसी में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण से रोकना ठीक नहीं था। सरकार की बहाने बाजी उनकी नकामी है। सुरक्षा की बात है तो जहां पेड़ पौधे हैं वहां जीवजंतु होंगे आज भी जेपीएनआईसी बिल्डिंग में समाजवादी सरकार का जो काम दिखाई देता है वह भाजपा के हर विकास को फोका कर रहा है।

महाकुंभ के लिए योगी सरकार ने की व्यापक तैयारियां

● सात मार्गों को केंद्र में रखकर सरकार ने यातायात के लिए तैयार की अलग-अलग योजनाएं

लखनऊ/प्रयागराज। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 के भव्य आयोजन के लिए योगी सरकार द्वारा की जा रही तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। योगी सरकार की कोशिश है कि श्रद्धालुओं को न सिर्फ महाकुंभ का आध्यात्मिक आनंद मिले, बल्कि उनकी यात्रा भी आसान और रोज सुविधाजनक हो। इस दिशा में राज्य सरकार ने विशेष रूप से सड़क मार्ग से प्रयागराज तक की पहुंच को सरल बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। सड़क मार्ग के विकास से लेकर पार्किंग, डिजिटल साइन बोर्ड, शटल बसें, ई-रिक्शा, और आपातकालीन योजनाओं तक, हर पहलू पर ध्यान दिया गया है। ये सभी कदम महाकुंभ 2025 को एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित, और यात्रागार आयोजन बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।

महाकुंभ 2025 के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के देशभर से प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद है और इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने 7 प्रमुख मार्ग चिह्नित किए हैं। इन मार्गों पर यातायात के सुगम प्रवाह के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा रही हैं, ताकि श्रद्धालु बिना किसी अवरोध के कुंभ नगरी तक पहुंच सकें। जिन 7 प्रमुख मार्गों को चिह्नित किया गया है उसमें जौपुर मार्ग से 21ब, वाराणसी मार्ग से 16ब, मिर्जापुर मार्ग से 12ब, रीवां मार्ग से 18ब, कानपुर मार्ग से 14ब, लखनऊ मार्ग से 10ब और अयोध्या-प्रतापगढ़ मार्ग से 9ब श्रद्धालुओं के आवागमन की संभावना है। इन सात मार्गों को केंद्र में रखकर सरकार ने यातायात के लिए अलग-अलग योजनाएं बनाई हैं। सामान्य दिनों और प्रमुख पर्वों के लिए यातायात की व्यवस्थाएं अलग होंगी। इन मार्गों पर एकल मार्ग (वन-वे) की व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे जाम की समस्या नहीं होगी और वाहनों का प्रवाह निबांध रहेगा। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए पार्किंग के

नाविकों व सफाई कर्मियों की बेटियों को को मिलेगा योजनाओं को लाभ

● 15 हजार सफाई कर्मियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ने का किया जा रहा है प्रयास

लखनऊ/प्रयागराज। योगी सरकार प्रयागराज में होने वाले महाआयोजन महाकुंभ 2025 को यादागर बनाने के साथ ही इस आयोजन में मुख्य भूमिका निभा रहे सफाई कर्मियों और नाविकों के जीवन स्तर को भी ऊपर उठाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उन्हें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ने के साथ ही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। वहीं, सफाई कर्मियों और नाविकों की बेटियों को प्रदेश सरकार की कन्या सुमंगला योजना और शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में सफाई कर्मियों और नाविकों और उनका परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। कुंभ 2019 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ मेला क्षेत्र के भ्रमण

लिए विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने 101 पार्किंग स्थलों का निर्माण सुनिश्चित किया है, जिनमें 5 लाख वाहनों के खड़ा होने की क्षमता होगी। इसमें 30 पार्किंग स्थल भारी वाहनों के लिए और 71 पार्किंग स्थल हल्के वाहनों के लिए चिह्नित किए गए हैं। इसके साथ ही, 20 पार्किंग स्थलों को सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां श्रद्धालुओं को सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस कदम से वाहनों की भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखा जा सकेगा। इसके अलावा, 67 जनपदीय पार्किंग स्थल और 34 मेला पार्किंग स्थल भी बनाए जाएंगे, ताकि श्रद्धालुओं को

के दौरान मेला में कार्य करने वाले सफाई कर्मियों एवं नाविकों को स्वच्छ सेवा सम्मान (स्वच्छ कुंभ, स्वच्छ आधार) प्रदान किया था। इसी उद्देश्य से यहां स्वच्छ कुंभ कोष की स्थापना की गई है। वर्तमान में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के माध्यम से इस कोष में 30 करोड़ से ज्यादा की धनराशि से यहां काम करने वाले सफाई कर्मियों और नाविकों के हितों का ध्यान रखा जा रहा है। उन्हें विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में अब तक 7798 को एलआईसी की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जोड़ा गया है, जिस पर करीब 2 करोड़ रुपए प्रीमियम अदा किया जा चुका है। इसी तरह, 12901 व्यक्तियों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से आच्छादित किया गया है, जिस पर 30 लाख रुपए प्रीमियम अदा किया जा चुका है। मेला एवं परेड क्षेत्र की वर्ष पर्यंत साफ सफाई इयत के लिए 144 सफाई कर्मियों तथा 1140 नाविक एवं माप मेला 2024 में तैनात किए गए 2500 सफाईकर्मों समेत महाकुंभ नरेंद्र मोदी ने कुंभ मेला क्षेत्र के भ्रमण

पार्किंग के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। महाकुंभ मेले का विशाल क्षेत्र और वहां पर लाखों श्रद्धालुओं का आवागमन एक बड़ी चुनौती होती है। इसे ध्यान में रखते हुए मेला क्षेत्र को 10 जोन में विभाजित किया जाएगा और इन सभी जोन को 30 पट्टून पुलों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। यह व्यवस्था इस तरह बनाई जा रही है कि श्रद्धालुओं को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही, मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं को सुगम आवागमन के लिए शटल बसें और ई-रिक्शा सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। कुल 550 शटल

कुंभ क्षेत्र को दिव्य-मत्स्य और नव्य स्वरूप प्रदान कर रही है योगी सरकार

● कुंभ मेला क्षेत्र में 30 अस्थायी थिमेटिक गेट्स की होगी स्थापना

लखनऊ/प्रयागराज। प्रयागराज में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ को योगी सरकार भव्य और दिव्य बनाने के लिए युद्धस्तर पर तैयारियों में जुटी है। कुंभ क्षेत्र में नदियों की बाढ़ की वजह से अभी तक कुंभ मेला प्रशासन का फोकस मेला की स्थाई तैयारियों की तरफ था लेकिन जैसे-जैसे नदियां बाढ़ का पानी तेजी से घट रहा है अब कुंभ क्षेत्र में अस्थायी कार्यों ने भी रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। इन अस्थायी कार्यों में कुंभ क्षेत्र का सौंदर्यकरण भी शामिल है। इसी क्रम में मेला क्षेत्र में थिमेटिक गेट्स का निर्माण किया जा रहा है। महाकुंभ में

सुरक्षा, सुविधा और स्वच्छता के साथ-साथ महाकुंभ की सुंदरता को लेकर भी योगी सरकार मिशन मोड में कार्य कर रही है। महाकुंभ से पहले ही प्रयागराज को दुर्लभ की तरह सजाया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि महाकुंभ के आयोजन के दौरान जब श्रद्धालु संगम नगरी पहुंचेंगे तो यहां की आभा देखकर न सिर्फ दंग रह जाएंगे, बल्कि श्री तरह धार्मिक आस्था के रंग में सराबोर हो जाएं। शहरी इलाके में सौंदर्यकरण की योजना पर कार्य गति पकड़ चुका है। लेकिन अब कुंभ क्षेत्र में सौंदर्यकरण की योजना पर कार्य शुरू हो गया है। प्रयागराज की क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह बताती हैं कि कुंभ क्षेत्र में सौंदर्यकरण की योजना के अंतर्गत 30 अस्थायी थिमेटिक गेट्स के निर्माण की योजना है। बाढ़ की वजह से यह कार्य रुका हुआ था लेकिन अब बाढ़ का पानी

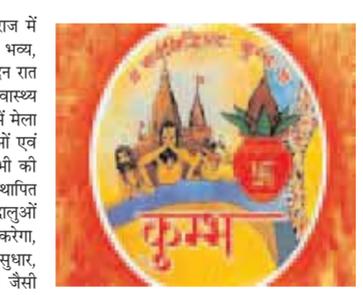
कम होते ही अस्थायी थिमेटिक गेट्स की स्थापना के लिए ईओआई (एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट) आमंत्रित किए गए हैं। अभी तक 10 फर्मों से अभिरूचि के साक्ष्य 600 गेटों की डिजाईन प्राप्त हुई हैं। इन 600 डिजाईन में से चयनित डिजाईनों के अनुसार वित्तीय निविदा प्रक्रियाधीन है। इन सभी गेट्स के निर्माण के लिए कुंभ की पौराणिक कथा के प्रसंग में समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों का चयन किया गया है। पौराणिक मूर्ति विज्ञान को आधार में रखकर इन गेट्स का निर्माण किया जायेगा। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी का कहना है कि कुंभ क्षेत्र में चारो दिशाओं में इनका इनका निर्माण होगा लेकिन मेला क्षेत्र के जिन सेक्टर में पर्यटकों और श्रद्धालुओं का आवागमन अधिक रहता है उनमें इन गेट्स के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी।

बाढ़ से प्रभावित अन्नदाताओं के लिए मसीहा बनी योगी सरकार

लखनऊ। योगी सरकार अन्नदाता किसानों की आय में वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है तो वहीं, उन्हें होने वाले नुकसान को भरपाई के लिए भी तत्पर रहती है। प्रदेश में बाढ़ की वजह से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए एक लाख करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है। सरकार ने प्रदेश के बाढ़ से प्रभावित रहे 34 जिलों के 3,12,866 किसानों को मुआवजा जारी किया है। सर्वाधिक मुआवजा लखीमपुर खीरी के किसानों को दिया गया है। यहां के 1.10 लाख से अधिक किसानों को 70 करोड़ से अधिक रुपये का मुआवजा दिया गया है। राहत आयुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के बाढ़ प्रस्त इलाकों में क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वे कराया गया अन्नदाताओं को समय से मुआवजा का भुगतान किया जा सके। नेपाल और पहाड़ी क्षेत्रों से छोड़े गये पानी से प्रदेश के 34 जिलों की 110989.26 हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई थी।

मेला क्षेत्र में होगी 'नेत्र कुम्भ' की स्थापना

लखनऊ/प्रयागराज। योगी सरकार प्रयागराज में होने जा रहे ऐतिहासिक महाकुंभ 2025 को भव्य, दिव्य, सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसी क्रम में मेला प्रशासन द्वारा महाकुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं एवं स्नानार्थियों के लिए नेत्र कुंभ की स्थापना भी की जा रही है। 9 करोड़ से अधिक धनराशि से स्थापित होने वाला यह नेत्र कुंभ (नेत्र शिविर) श्रद्धालुओं को एक अस्थायी नेत्र देखभाल सुविधा प्रदान करेगा, जहां मेले के दौरान श्रद्धालुओं की दृष्टि सुधार, मोतियाबिंद सर्जरी और चरम का वितरण जैसी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। नेत्र कुंभ के लिए एक बड़ी केंद्रीय इकाई मुख्य मेला क्षेत्र में स्थापित की जाएगी जो प्राथमिक नेत्र देखभाल केंद्र के रूप में कार्य करेगी।



महाकुंभ 2025 में रिकॉर्ड संख्या में पूरे देश और दुनिया से श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। योगी सरकार और मेला प्रशासन इन श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए अपनी ओर से शत प्रतिशत प्रयास कर रहा है। नेत्र कुंभ की स्थापना उसी दिशा में उन्नयन का कदम है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 9.15 करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रस्तावित किया गया है। इसके माध्यम से महाकुंभ के दौरान

अंदर ही स्थापित किया जाएगा। इस नेत्र कुंभ में तीर्थयात्रियों और संतों की व्यापक स्तर पर आंखों की जांच सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए शिविर में नेत्र परीक्षण के लिए आवश्यक आधुनिक उपकरणों को लगाया जाएगा। जांच के दौरान दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों को चरम वितरित किया जाएगा, जबकि जिन मामलों में अधिक गंभीर समस्या पाई जाएगी वहां भागीदार अस्पतालों में मोतियाबिंद सर्जरी और अन्य आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी। नेत्र देखभाल सेवाओं के साथ-साथ पहल का उद्देश्य लोगों को नेत्र स्वास्थ्य और नियमित जांच के महत्व को समझाना और उन्हें शिक्षित करना है। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों की जांच के माध्यम से एकत्र किए गए नेत्र स्वास्थ्य डाटा को डिजिटली सेव किया जाएगा। इससे रोगियों की स्थिति पर नजर रखने और आवश्यकता पड़ने पर इसका फॉलोअप किया जा सकेगा और आवश्यक देखभाल प्रदान करने में मदद मिलेगी। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। यहां पर्याप्त संख्या में नेत्र विशेषज्ञों को भी नियुक्त किया जाएगा और आवश्यक उपकरणों के साथ ही पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की भी उपलब्धता रहेगी।

